



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2820]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 25, 2018/श्रावण 3, 1940

No. 2820]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 25, 2018/SHRAVANA 3, 1940

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2018

**का.आ. 3595(अ).**—जबकि, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत जारी दिनांक 16.12.2016 के का.आ. संख्या 4161 (अ) की भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा (इसे इसके बाद इसे उक्त अधिनियम कहा गया है) जिसे दिनांक 23.12.2016 के भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य में मैसर्स आंध्र प्रदेश गैस डिस्ट्रीब्यूशन कार्पोरेशन लि. द्वारा पश्चिम गोदावरी जिले में अंबरपेटा में गेल एसवी-5 एम के जरिए सैंटिनी सैनिटरीवेयर प्रा. लि. को प्राकृतिक गैस की दुलाई हेतु पाइपलाइन बिछाने के उद्देश्य के लिए उस अधिसूचना के साथ संलग्न परिशिष्ट में भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन करने का अपना इरादा घोषित किया था;

और जबकि भारत सरकार अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के बाद और इस बात से संतुष्ट होने पर कि उक्त भू-खंड उनमें प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन करने हेतु पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित थे;

और जबकि अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने दिनांक 11.04.2017 के भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 29.03.2017 की भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1137(अ) के अनुसार उक्त पाइपलाइन बिछाने के लिए उस अधिसूचना के साथ में संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार के अर्जन की घोषणा की थी;

और, इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने पाइपलाइन बिछाने के लिए उक्त भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार संबंधी घोषणा के प्रकाशन की तारीख को भारत सरकार के स्थान पर मैसर्स आंध्र प्रदेश गैस डिस्ट्रीब्यूशन कार्पोरेशन लि. में निहित होने और इसके सभी ऋणधारों से मुक्त होने की घोषणा की थी;

और जबकि, मैसर्स आंध्र प्रदेश गैस डिस्ट्रीब्यूशन कार्पोरेशन लि. ने पाइपलाइन बिछाने समय प्रयोक्ता के अधिकार में भूस्वामियों और प्रयोक्ता के अधिकार की चौड़ाई को 20 मीटर से घटाकर 10 मीटर करने का विरोध किया और अभ्यावेदन दिया। मैसर्स आंध्र प्रदेश गैस डिस्ट्रीब्यूशन कार्पोरेशन लि. ने भूस्वामियों के अनुरोध की जांच की है और प्रयोक्ता के अधिकार की चौड़ाई को 20 मीटर से घटाकर

10 मीटर करने के लिए दिनांक 17.05.2017 को अपनी सहमति प्रस्तुत कर दी है। प्रयोक्ता के अधिकार को चिन्हित किया गया था और प्रयोक्ता के अधिकार में आने वाले परिमाणों को परिकलित किया गया था।

श्री मल्लीना शेषगिरी राव पुत्र श्री रंगा राव, सर्वेक्षण संख्या 208 और 207 के एम.नागुलापल्ली गांव के भू-स्वामी ने दिनांक 23.12.2016 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 16.12.2016 की उपर्युक्त 3(1) अधिसूचना, का.आ. संख्या 4161 (अ) के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील की थी और माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को मौखिक आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर दिए जाने और उसकी मौखिक आपत्तियों पर कानून के अनुसार विधिवत रूप से अंतिम आदेशों के अनुसार कार्रवाई करने का आदेश पारित किया।

और जबकि, सक्षम प्राधिकारी ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों में सम्मिलित श्री मल्लीना शेषगिरी राव की भूमियों के लिए संशोधित 6(1) प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

और जबकि, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

और जबकि, भारत सरकार, ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने और इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि उक्त भूमि उपर्युक्त पाइपलाइन को बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें प्रयोक्ता के अधिकार के अर्जन का निर्णय लिया है।

अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्वारा इस अधिसूचना की संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में प्रयोक्ता का अधिकार अर्जित किया जाता है।

और आगे, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा निदेश जारी करती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए उक्त भूमि में प्रयोक्ता का अधिकार भारत सरकार में निहित करने के बजाए, घोषणा के प्रकाशन की तारीख को मैसर्स आन्ध्र प्रदेश गैस डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी, और यह सभी ऋणधारों से मुक्त होगा।

### अनुसूची

आन्ध्र प्रदेश गैस डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
गेल एसवी-5 एम.नागुलापल्ली से सेनटिनी सैनिटैरियेयर प्राइवेट लिमिटेड  
अंबरपेटा तक गैस पाइपलाइन

जिला	मंडल	गांव	आर. एस. संख्या	दिनांक 11.04.2017 को प्रकाशित दिनांक 29.03.2017 के का.आ. संख्या 1137 द्वारा पीएंडएमपी अधिनियम, 1962 की धारा 6 (1) के तहत अधिसूचित क्षेत्र हेक्टेयर में	पीएंडएमपी अधिनियम, 1962 की धारा 6 (1) के तहत प्रकाशन के लिए अब अपेक्षित क्षेत्र हेक्टेयर में
पश्चिम गोदावरी	द्वारका तिरूमाला	एम.नागुलापल्ली	208	0.146	0.101
			207	0.138	0.049
योग				0.284	0.150

[फा. सं. एल-14014/31/2016-जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd July, 2018

**S.O. 3595(E).**—Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 4161(E) dated 16.12.2016 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated 23.12.2016, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through GAIL SV-5 M. Nagulapalli to Sentini Sanitaryware Private Limited, Amberpeta of West Godavari District by M/s Andhra Pradesh Gas Distribution Corporation Limited in the State of Andhra Pradesh;

And whereas Government of India, after considering the report submitted by the Competent Authority under sub-section (1) of Section 6 of the Act and on being satisfied that the said lands were required for laying the pipeline to acquire the Right of User therein;

And whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Act, Government of India declared acquisition of the Right of User in land, specified in the schedules appended to that notification for laying the said pipeline, vide notification of Government of India in Ministry of Petroleum & Natural Gas number S.O. 1137(E) dated 29.03.2017 published in the Extraordinary Gazette of India dated 11.04.2017;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India declared vesting the Right of User in the said land for laying the pipeline in M/s Andhra Pradesh Gas Distribution Corporation Limited, instead of Government of India free from all encumbrances on the date of publication of declaration;

And whereas, while laying the pipeline by M/s Andhra Pradesh Gas Distribution Corporation Limited, the land owners in the Right of User obstructed and represented to reduce the width of Right of User from 20 mtrs. to 10 mtrs. M/s Andhra Pradesh Gas Distribution Corporation Limited has examined the request of the land owners and furnished consent on 17.05.2017 to reduce the width of Right of User from 20 mtrs. to 10 mtrs. The Right of User was earmarked and extents fallen in Right of User were calculated;

Shri Mallina Seshagiri Rao s/o Shri Ranga Rao, a land owner of M.Nagulapalli Village land owner of Survey No. 208 & 207 approached the Hon'ble High Court against the said 3(1) notification having S.O. No. 4161(E) dated 16.12.2016 published in the Extra Ordinary Gazette of India dated 23.12.2016 and the Hon'ble High Court passed orders to give opportunity to the petitioner to represent oral objections and to take action as per law duly issuance of final orders on his oral objections.

And whereas, the Competent Authority has furnished revised 6(1) proposal to the lands of Shri Mallina Seshagiri Rao covered in the orders of the Hon'ble High Court.

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India

And whereas the Government of India, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the said pipeline, has decided to acquire Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Government of India, vest on the date of publication of the declaration, in M/s Andhra Pradesh Gas Distribution Corporation Limited, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

Andhra Pradesh Gas Distribution Corporation Limited  
Gas Pipeline from GAIL SV-5 M. Nagulapalli to Sentini Sanitaryware Private Limited,  
Amberpeta

District	Mandal	Village	R.S. No.	Area notified under Section 6(1) of P&MP Act, 1962 vide S.O. No. 1137 dated 29.03.2017 published on 11.04.2017 Hc. Are	Area now required for publication under Section 6(1) of P&MP Act, 1962 Hc. Are
West Godavari	Dwaraka Tirumala	M. Nagulapalli	208	0.146	0.101
			207	0.138	0.049
Total				0.284	0.150

[F.No. L-14014/31/2016-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.